

‘सिंधु जल समझौते से बचने वाला पानी बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरु को मिलेगा’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने गुसाईंसर बड़ा में अंत्योदय के शिविर का अवलोकन किया

बीकानेर, 8 जुलाई (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से रह हुए सिंधु जल समझौते से बचने वाला पानी बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरु को मिलने वाला है। ये चारों जिले बड़े सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए हैं, वो सभी पूरे होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता आए तो पृष्ठना कि उनके वादों का क्या हुआ।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बीकानेर के गुंसाईंसर बड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करने के बाद आयोजित सभा को संबोधित किया। उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़ भी थे।

■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा की, लेकिन हम श्री डूंगरगढ़ में ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम करेंगे।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि श्रीडूंगरगढ़ के लिए जमीन देने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए जरूरी बजट भी दिया जायेगा। कांग्रेस ने जिस व्यापारी से घोषणा कराई थी, वो ये काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा की, लेकिन हम ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने व्यापारी पर दबाव बनाकर सिर्फ घोषणा करवा ली, अब वो टालमटोल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि जब तक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भला नहीं होगा, तब तक राजस्थान उत्कृष्ट नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इंदिरा गांधी नहर के लिए चार हजार



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के गुंसाईंसर बड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण किया और सभा को संबोधित किया।

करोड़ रूपए दिए हैं और बीकानेर, चूरु, श्रीगंगानगर में इससे काम होगा। किसान को पानी-बिजली और बीज देने का काम हमारी सरकार ने किया है।

विधायक ताराचंद सारस्वत ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री के समक्ष

ट्रॉमा सेंटर बनाने की मांग रखी तथा सरकारी कॉलेज की घोषणा करने की मांग की।

ताराचंद सारस्वत के भाषण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके विधायक होशियार हैं। दो मिनट का बोला था,

लेकिन पूरे तीन पन्ने का भाषण बोल दिया।

उन्होंने अपनी सभी मांगें रख दी हैं। जो काम अधूरे हैं, उनके बारे में भी बोल दिया और जो करवाने हैं, उनके बारे में भी बोल दिया।

उदयपुर फाइल्स फिल्म पर प्रतिबंध की माँग पर सुनवाई आज होगी

— **—**

चिराग तो अब विपक्षी नेताओं जैसी भाषा बोल रहे हैं। यह चौकाने वाला है।

हालाँकि अभी तो चुनाव में समय है, देखना यह होगा कि चिराग नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ अपनी बयानबाजी को कितना आगे ले जाते हैं। यह भी देखने की बात है कि क्या वे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिये लोकसभा संसद और केन्द्रीय मंत्री पद से वाकई इस्तीफा दे देंगे या फिर वे सीट बंटवारे में अच्छी डील हासिल कर के पीछे हट जाएँगे?

जो भी हो, एनडीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अपने वाले हफ्तों में तकरार तेज होने की पूरी संभावना है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म और उसके ट्रेलर पर बैन लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है

कहानी हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच गंभीर दूरी और तनाव पैदा कर सकती है। याचिका की 9 जुलाई, बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है।

याचिका में कहा गया है, “फिल्म का ट्रेलर मुस्लिम समुदाय को नकारात्मक तरीके से पेश करता है, जिससे उस समुदाय के लोगों के सम्मान से जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है। फिल्म बहुत भड़काऊ है और दो समुदायों के बीच फूट डाल सकती है, जिससे देशभर में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है।

याचिका कहती है कि “ट्रेलर की सामग्री खास तौर पर मुस्लिम समुदाय

■ **यह फिल्म उदयपुर में दिन दहाड़े हुई कन्हैयालाल दर्जी की नृशंस हत्या पर आधारित है। ज्ञातव्य है कि मुस्लिम कट्टरपंथी युवकों ने तलवारों से काट कर कन्हैयालाल की हत्या कर दी थी।**

■ **जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि फिल्म से हिंदू-मुस्लिम वैमनस्पर्ता को बढ़ावा मिलेगा और इससे देश भर में शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है।**

■ **फिल्म 11 जुलाई को रिलीज हो रही है।**

को निशाना बनाती दिखती है, जिसमें उनके बारे में गलत और तोड़ी-मरोड़ी गई बातें दिखाकर भाईचारे को तोड़ने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की

बिहार में 47 प्रतिशत मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा करवाए

नयी दिल्ली, 08 जुलाई। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में दो सप्ताह के अंदर चुनाव अधिकारियों को लगभग आधे मतदाताओं (47 प्रतिशत) के भरे हुए गणना-फार्म प्राप्त हो चुके हैं। यह जानकारी मंगलवार को आयोग द्वारा जारी एक विज्ञप्त में दी गयी। गणना-फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है। आयोग ने कहा है कि बिहार में पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत 3,70,77,077 गणना फार्म मिल चुके हैं, जो राज्य में कुल 7,89,69,844 मतदाताओं की संख्या का 46.95 प्रतिशत है। आयोग ने पुनरीक्षण के लिए दिशानिर्देश गत 24 जून को जारी किए थे। आयोग ने पुनरीक्षण के काम के लिए इन दो सप्ताह में 7.90 करोड़ फॉर्म मुद्रित कराए हैं और सूची में दर्ज 97 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं (7,70,44,990) के गणना-फार्म वितरित किए जा चुके हैं। आयोग का कहना है कि अब तक 18.16 प्रतिशत फॉर्म उसके ऐप ईसीआईनेट पर अपलोड किए जा चुके हैं।

अश्वनी पंजाब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वहीं, अब भाजपा के संगठनात्मक ढाँचे को देखते हुए अश्वनी शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना रणनीतिक फैसला माना जा रहा है।

ट्रंप ने 14 देशों के लिए नए टैरिफ घोषित किए

ट्रंप ने इन सभी 14 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को पत्र भेजकर सूचित कर दिया है

वाशिंगटन, 08 जुलाई। वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ाने वाले नए कदम में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बंगलादेश और म्यांमार सहित 14 देशों पर नए टैरिफ की घोषणा की है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब वाइट हाउस द्वारा शुरू किए गए कुछ सबसे आक्रामक आयात करों पर 90-दिवसीय रोक इस सप्ताह समाप्त होने वाली थी। ट्रंप ने जिन 14 देशों के नेताओं को औपचारिक पत्र भेजे हैं, उनमें सहयोगी और छोटे देश भी शामिल हैं। यह पत्र इस साल एक अगस्त को लागू होने वाले टैरिफ के बारे में हैं, जो ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों को दर्शाता है। पत्र में ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया से आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की अपनी धमकी दोहराई और एक अगस्त से शुरू होने वाले संभावित शुल्कों के बारे में अन्य विश्व नेताओं को सूचित किया। उच्च टैरिफ शुरू में नौ जुलाई से प्रभावी होने वाले लेकिन अधिकारियों द्वारा नए व्यापार सौदों पर बातचीत करने की मांग के

■ **इन देशों में जापान व दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देशों के अलावा म्यांमार, बांग्लादेश जैसे छोटे देश भी शामिल हैं। कई देश तो ऐसे हैं जो लम्बे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे हैं।**

कारण इन्हें निर्लांबित कर दिया गया था। ट्रंप ने 'दृढ़ सोशल प्लेटफॉर्म' पर जापान और दक्षिण कोरिया को लिखे पत्र में कहा, यदि किसी कारण से आप अपने टैरिफ बढ़ाने का फैसला करते हैं, तो आप उन्हें जिस भी संख्या में बढ़ाना चाहते हैं, वह हमारे द्वारा लगाए जाने वाले 25 प्रतिशत में जोड़ दिया जाएगा। गौरतलब है कि उच्च टैरिफ एक अगस्त से प्रभावी होंगे और विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, स्टील और एल्यूमीनियम जैसे पहले से घोषित सेक्टर टैरिफ के साथ नहीं जुड़ेंगे।

ट्रंप के पत्रों में जापान और दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी गई थी कि उनके टैरिफ में किसी भी वृद्धि के साथ ही अमेरिकी शुल्कों में भी वृद्धि की जाएगी। ट्रंप ने घोषणा की कि इसी तरह के पत्र

12 अन्य देशों के नेताओं को भेजे गए, जिनमें मलेशिया, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, लाओस, टय्नीसीया, इंडोनेशिया, बंगलादेश, सर्बिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, कंबोडिया, थाईलैंड शामिल हैं। उन्हें यह सूचना दी गई कि अगले महीने से उन पर 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाएंगे। मलेशिया, कजाकिस्तान और ट्यूनीशिया पर टैरिफ दर 25 प्रतिशत होगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका और बिर्हाना के लिए यह 30 प्रतिशत होगी। इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत और बांग्लादेश एवं सर्बिया पर 35 प्रतिशत टैरिफ दर लागू होगी। कंबोडिया और थाईलैंड पर टैरिफ दर 36 प्रतिशत होगी, जबकि लाओस एवं म्यांमार पर यह 40 प्रतिशत तक होगी।

कांग्रेस ने माना कर्नाटक में पार्टी में अन्तर्कलह है

- **कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला ने कहा, कई विधायकों को पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से शिकायत है।**
- **लेकिन सुरजेवाला ने नेतृत्व परिवर्तन से इन्कार किया व कहा कि इस पर फैसला हाईकमान ही ले सकता है।**

मैंने उनसे कहा है कि वे ये सब मुझे लिखित में दें। हम उनका बारी बारी से हल निकालेंगे।

कांग्रेस नेतृत्व का दावा है कि राज्य में पार्टी में हालात नाकाम हैं हैं लेकिन आम चर्चा यह है कि शिकायतों के सामने आने से पार्टी की अंदरूनी कलह दिखने लगी है। अब सुरजेवाला ने जो रुख अपनाया है, वह बंद कम्परे में बातचीत

और मीडिया की निगाहों से दूर रहने का प्रयास है। उन्होंने समस्या के हल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है, जिससे लगता है कि पार्टी शिकायतों के निपटारे के मामले में कोई गंभीर कदम उठाने वाली नहीं है।

राज्य में नेतृत्व बदलाव को लेकर उठे सवालों को दरकिनार करते हुए, उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा, एक

पत्रकार की संपादक बनने की आकांक्षा हो सकती है, लेकिन इस फैसले की डोर तो चैनल मालिक के हाथ में होती है। सुरजेवाला के बयान नेतृत्व संबंधी फैसलों पर कांग्रेस हाईकमान की मजबूत पकड़ को दिखाते हैं।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के दिल्ली दौरे के बारे में पूछे जाने पर, सुरजेवाला ने स्पष्ट किया कि ये दौरे पूरी तरह से प्रशासनिक हैं। उन्होंने कहा, "वे सरकारी काम से दिल्ली जा रहे हैं—ताकि वे केन्द्र के समक्ष कर्नाटक के मसले रख सकें। यह उनका कर्तव्य है और वे इसे पूरा कर रहे हैं।"

चिराग पासवान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हत्याएं और अन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यह मेरे लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि जिस सरकार का मैं समर्थन करता हूँ, वह सुशासन के लिए जानी जाती है।

चिराग तो अब विपक्षी नेताओं जैसी भाषा बोल रहे हैं। यह चौकाने वाला है।

हालाँकि अभी तो चुनाव में समय है, देखना यह होगा कि चिराग नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ अपनी बयानबाजी को कितना आगे ले जाते हैं। यह भी देखने की बात है कि क्या वे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिये लोकसभा संसद और केन्द्रीय मंत्री पद से वाकई इस्तीफा दे देंगे या फिर वे सीट बंटवारे में अच्छी डील हासिल कर के पीछे हट जाएँगे?

जो भी हो, एनडीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अपने वाले हफ्तों में तकरार तेज होने की पूरी संभावना है।

इज़रायल के प्र.मंत्री... ‘पुलवामा हमले के लिए विस्फोटक एमेज़ॉन से खरीदे गए थे’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तनाव कम कराने तथा सर्बिया और कोसोवो के बीच समझौता कराने में उनके प्रयासों को अन्देखा किया। हालांकि भारत ने अधिकारिक रूप से पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए संघर्ष में ट्रंप की भूमिका का खंडन किया है और कहा है कि आपसी बातचीत से समाधान हुआ।

ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मिश्र, बर्मा, इथियोपिया के बीच शांति बनाए रखने में मदद की है, और अब्राहम समझौते (अब्राहम काईड) के जरिए इज़राइल और कुछ अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने में भी उनकी भूमिका रही है।

ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में

खुद को एक शांति निर्माता बताया था और वादा किया था कि वे अपने बातचीत के कौशल से यूक्रेन और गाज़ा के युद्धों को जल्दी खत्म करवा देंगे। लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने के पांच महीने बाद भी ये दोनों संघर्ष जारी हैं।

नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हुई बातचीत में गाज़ा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर एक समझौते पर काम करने पर चर्चा हुई। उसी दौरान, इज़राइल के अधिकारी कतर में हमास के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता कर रहे थे, जिसमें अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। ट्रंप ने बैटक से पहले ही अनुमान जताया था कि इस सप्ताह एक समझौता हो सकता है।

सुधार के माध्यम से नवीकरण (रिन्यूअल थ्रू रिफॉर्म) आज की युवा पीढ़ी और दोनों दलों के उदार सोच वाले लोगों में सुधार की मांग तेज हो रही है। जहाँ संविधान संशोधन मुश्किल प्रतीत होते हैं, वहीं विधायी और प्रक्रियागत बदलावों से सत्ता का संतुलन लौटाना साध्यपत किया जा सकता है और भरोसा दौड़ाना जा सकता है।

दूसरा है, गहराता घुवीकरण (डीपनिंग पोलराइजेशन)। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह निकट भविष्य का सबसे संभावित रास्ता लगता है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट समर्थक अब लगभग दो अलग-अलग देशों में रह रहे हैं—जिनके मूल्य, कानून और भविष्य की कल्पना एक-दूसरे से उकराती हैं। अगर कोई भी पक्ष चुनावी हार को स्वीकार नहीं कर पाता, तो लोकतंत्र की वैधता ही समाप्त हो जाएगी।

तीसरा है, अधिनायकवाद की ओर झुकाव

(अर्थोरेटरियनड्रिफ्ट)। अगर संस्थागत मानदंड और कमजोर होते गए, तो अमेरिका एक “साफ्ट ऑथोरिटरियन” यानी नरम तानाशाही की ओर फिसल सकता है, जहाँ एक पार्टी का वर्चस्व हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर हो, और असहमति को अपराध मान लिया जाए। ज़रूरी स्थितियों पहले से मौजूद हैं तथा अब बस इरादे की ज़रूरत है।

लेकिन, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका का इतिहास लचीलेपन और पुनर्निर्माण का रहा है। सिविल वॉर से लेकर वॉटरगेट तक, अमेरिका ने ऐसे संकटों का सामना किया है, जो अजेय लगते थे। सवाल यह है कि क्या यह देश एक बार फिर अपने आत्मबल से खुद को सुधार संकेगा, इससे पहले कि दरारें टूटन में बदल जाएँ।

कुल मिलाकर, अमेरिकी तंत्र के भविष्य को न तो सिर्फ अदालतें तय कर सकती हैं, और न सिर्फ

बैलट बॉक्स में। अमेरिकन व्यवस्था का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि क्या इसके नागरिक और नेता दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर उन गहरे मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं, जो इस गणराज्य को एक सूत्र में बाँधते हैं। और वे मूल्य हैं— निष्पक्षता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति साझा प्रतिबद्धता।

अगर ऐसा नहीं हो सका, तो खतरा विदेशी नहीं होगा, वह भीतर से ही आएगा। इलेक्ट्रिक कारों से लेकर अंतरिक्ष शोध तक के उद्योगों को झकझोर देने वाले अरबपति उद्यमी एलन मस्क अब एक नई दिशा में, अमेरिकन राजनीति में कदम रख चुके हैं। अपनी नई राजनीतिक पार्टी, “अमेरिका पार्टी” की शुरुआत के साथ, मस्क ने लोकतांत्रिक इतिहास की मजबूत प्रहरि, अमेरिकी द्वि-दलीय व्यवस्था की जड़ों को चुनौती देने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने यह कदम ऐसे समय पर उठाया

है, जब डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों से जनता का मोहभंग ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच चुका है। लेकिन क्या “अमेरिका पार्टी” सच में उस दो-ध्रुवीय प्रभुत्व को हिला सकती है, जो पिछले 160 से अधिक वर्षों से अमेरिकी राजनीति को आकार देता आया है? दोनों बड़ी पार्टियों से असंतोष लगातार बढ़ रहा है। हाल की एक गैलप सर्वे के मुताबिक, लगभग 63 प्रतिशत अमेरिकियों का मानना ​​है कि एक तीसरी पार्टी की ज़रूरत है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मतदाता मौजूदा व्यवस्था को अव्यवस्थित, अत्यधिक घुबुकीृत और आम नागरिकों को वास्तविक वित्ताओं से कटी हुई मानते हैं। दक्षिणपंथ एवं वामपंथ दोनों की बढ़ती जा रही शुरुआत (पॉपुलिस्ट) भावनाओं ने राजनीतिक नेतृत्व और जनता के बीच की खाई को उजागर कर दिया है। यह स्थिति किसी भी नई राजनैतिक ताकत के लाभ के लिए एक दुर्लभ

है, जब डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों से जनता का मोहभंग ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच चुका है। लेकिन क्या “अमेरिका पार्टी” सच में उस दो-ध्रुवीय प्रभुत्व को हिला सकती है, जो पिछले 160 से अधिक वर्षों से अमेरिकी राजनीति को आकार देता आया है? दोनों बड़ी पार्टियों से असंतोष लगातार बढ़ रहा है। हाल की एक गैलप सर्वे के मुताबिक, लगभग 63 प्रतिशत अमेरिकियों का मानना ​​है कि एक तीसरी पार्टी की ज़रूरत है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मतदाता मौजूदा व्यवस्था को अव्यवस्थित, अत्यधिक घुबुकीृत और आम नागरिकों को वास्तविक वित्ताओं से कटी हुई मानते हैं। दक्षिणपंथ एवं वामपंथ दोनों की बढ़ती जा रही शुरुआत (पॉपुलिस्ट) भावनाओं ने राजनीतिक नेतृत्व और जनता के बीच की खाई को उजागर कर दिया है। यह स्थिति किसी भी नई राजनैतिक ताकत के लाभ के लिए एक दुर्लभ

सुअवसर प्रस्तुत कर रही है।

एलन मस्क एक ऐसे उभरते गठजोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। जो पारंपरिक राजनीतिक पहचान से परे है। उनकी नजर तकनीकी उद्यमियों, जो दोनों पार्टियों से निराश हैं, और युवा मतदाताओं पर है। “अमेरिका पार्टी” उन मतदाताओं का ठिकाना बन सकती है, जो आर्थिक रूप से व्यवहारिक सोच रखते हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से प्रगतिशील सोच और दक्षिणपंथी अतिवाद, दोनों से सतर्क हैं।

अभी केवल इतना कहा जा सकता है कि चाहे “अमेरिका पार्टी” द्वि-दलीय प्रणाली को गिरा पाए या केवल उसमें सुधार के लिए एक धक्का दे, लेकिन एलन मस्क ने एक नई चर्चा की शुरुआत कर दी है। एक ऐसा देश जहाँ राजनीतिक कल्पना अक्सर जड़ जमाकर बैठ जाती है, वहाँ यह खुद में एक ऐसा झटका है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।